बर्षः- 05
अंकः- 297
मुरादाबाद
(Thursday)
19 February 2026
पृष्ठः-8
मूल्यः- 3.00 रूपया

दैनिक प्रातः कालीन

क्यूँ न लिखूँ सच

मुरादाबाद से प्रकाशित
भारत सरकार से रजिस्टर्ड
RNI No.UPBIL/2021/83001
राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, बहराइच, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

स्पेन और फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष से मिले पीएम मोदी, बोले- भारत-यूरोप FTA से सुनहरे युग की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और फिनलैंड के पीएम पेटेरी ओर्पो से बैठक में भारत-यूरोपियन एफटीए को स्वर्ण युग बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के साथ रक्षा, तकनीक और डुअल ईयर ऑफ कल्चर, पर्यटन व एआई पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को भारत-यूरोप संबंधों में स्वर्ण युग लाने वाला बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्पेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक में दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने, खासकर रक्षा, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।2026 को भारत और स्पेन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने बताया कि इस दौरान भारतीय और स्पेनिश विश्वविद्यालयों की बड़ी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगी, जो लोगों को जोड़ने में मदद करेगी।

भारत-यूरोप संबंध पर क्या बोले पीएम मोदी- इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपीय एफटीए से भारत और स्पेन के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। दोनों नेताओं ने टाटा-एयरबस सहयोग के तहत सी-295 परिवहन विमान की अंतिम असेंबली लाइन की सफलता का भी स्वागत किया। उन्होंने भारत-स्पेन डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सह-निर्माण और सह-उत्पादन आधारित रक्षा सहयोग को भी भविष्य की दिशा बताया।बता दें कि स्पेन के राष्ट्रपति इस आधिकारिक दौरे पर 18 से 19 फरवरी तक भारत में हैं। सांचेज ने समिट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके परिणाम वैश्विक एआई गवर्नेंस को आकार देने में मदद करेंगे। उन्होंने शिक्षा में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की, खासकर भारत की नई शिक्षा नीति के तहत।

पीएम मोदी और सांचेज के बीच बैठक-पीएम मोदी और सांचेज ने पर्यटन, व्यापार, निवेश, तकनीक, नवाचार, जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने स्पेनिश विश्वविद्यालयों और संस्थानों को एसटीईएम और तकनीकी क्षेत्रों में भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और स्पेन के भारत-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की बात पर भी चर्चा की।फिनलैंड के पीएम के साथ बैठक में क्या-क्या?- इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ भी बैठक की। उन्होंने एफटीए के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-फिनलैंड व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने 6त्र, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने डिजिटलाइजेशन और सतत विकास को भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए अहम बताया और टेक्नोलॉजी कंपनियों के आपसी निवेश का स्वागत किया। उन्होंने वैश्विक शासन और सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए।

संक्षिप्त समाचार

अपने पैतृक गांव पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव, कहा- भतीजी की शादी के बाद देंगे सारे सवालों के जवाब

जमानत पर जेल से रिहा हुए अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। वह चार पांच दिन यहीं रहेंगे। उनकी भतीजी की शादी है। उन्होंने कहा कि भतीजी की शादी के बाद वह सारे सवालों के जवाब देंगे।

चेक बाउंस मामले में जमानत पर जेल से रिहा हुए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को शाहजहांपुर जिले में अपने पैतृक गांव कुंडरा में पहुंचे। उन्होंने भतीजी की शादी की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वह दो दिन भतीजी की शादी में व्यस्त हैं। चार दिन बाद सभी के सवालों का जवाब देंगे।फिल्म अता-पता-लापता बनाने पर खर्च धनराशि को लेकर उद्योगपति माधौ गोपाल अग्रवाल व अभिनेता राजपाल यादव का विवाद न्यायालय में पहुंच गया। पांच करोड़ रुपये का ऋण ब्याज सहित नौ करोड़ रुपये हो गया था। न्यायालय के आदेश पर पांच फरवरी को अभिनेता ने सरेंडर कर दिया। जेल जाने से पहले उन्होंने भावुक अपील की थी, जिसके बाद उन्हें मदद के लिए बॉलीवुड समेत तमाम लोग आए थे। 12 दिन जेल में रहने के बाद मंगलवार को जमानत पर बाहर आ गए। बुधवार को तड़के पैतृक गांव आ गए। वह 19 फरवरी को बड़े भाई श्रीपाल की बेटी प्रियंका की शादी में शामिल होंगे। उन्होंने बरात की तैयारियों को देखा। राजपाल ने मदद करने वालों का किया शुक्रिया - राजपाल यादव ने कहा कि सारी प्रक्रिया हाईकोर्ट से चल रही हैं। हाईकोर्ट के निर्णय का पूरा

मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लडने का किया एलान, गेस्ट हाउस कांड को याद कर कही बात

मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का एलान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सम्मान के लिए अंबेडकरवादी लोग देशभर में जुट जाएं। दिल्ली में टाइप-8 बंगला अलाट होने के पीछे उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बाद बढ़ा सुरक्षा खतरा बताया। राजधानी लखनऊ में बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इन दिनों लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने के बजाय अर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (AI) को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाएं चल रही हैं।बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में जैसे-जैसे चुनाव पास आएंगे, जो लोग हमारे खिलाफ हैं, वे हमें सत्ता से दूर रखने की और भी कोशिश करेंगे। हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। सिर्फ यूपी में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी अंबेडकरवादियों को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का आत्म-सम्मान पाने के आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहना चाहिए।संकीर्ण व अंबेडकर विरोधी है पार्टियों की सोच- उन्होंने कहा कि बसपा के यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने की बात फेक न्यूज है। यह बिल्कुल गलत, झूठ, हवा-हवाई व मनगढ़ंत है। बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। बसपा के लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि पार्टियों की सोच संकीर्ण व अंबेडकर विरोधी है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें करते रहते हैं। पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता हाथी की मस्त चाल चलते रहें। 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़कर फिर से बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली के बंगले पर कहा कि मेरी सुरक्षा के हिसाब से लंबे समय बाद टाइप-8 बंगला अलाट हुआ है। इसे मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन, कुछ लोग इसके बारे में भी गलत व गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हैं। इससे भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गेस्ट हाउस कांड में जानलेवा हमला हुआ- उन्होंने कहा कि सपा सरकार व इनके मुखिया के इशारे पर ही दो जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद 03 जून 1995 को बसपा के नेतृत्व में यूपी में पहली सरकार बनी। उसी समय से सुरक्षा कारणों से मुझे तत्कालीन भारत सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा दी गई थी। वह सुरक्षा खतरा कम होने के बजाय अब और भी बढ़ गया है। इस नाते टाइप-8 का बंगला मिला है।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोलीं, पिछली सरकारों में ठेके पर नकल होती थी, योगी सरकार में अब कोई सोच नहीं सकता

यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षार्थियों का उत्साह बढ़ाया।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बुधवार को पहले दिन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जिया मऊ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को फूल देकर स्वागत किया।इस दौरान मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में ठेके पर नकल होती थी लेकिन योगी सरकार में अब कोई सोच भी नहीं सकता। यदि कहीं ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी सोचा न गया हो। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों से कहां की आप हमारे भविष्य है, देश का गौरव हैं। चिंता मुक्त

होकर परीक्षा दें यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मंत्री ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। छात्राओं को टीका चंदन करते हुए पेड़ा खिलाकर मुंह मीठा कराया गया।माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने बताया कि साल 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित की जा रही हैं। प्रथम पाली (प्रातः 8:30 बजे से 11:45 तक) हाईस्कूल में हिंदी एवं प्रारम्भिक हिंदी की परीक्षा हो रही है। राजधानी सहित प्रदेश भर में कुल 8,033 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी जिसमें कुल 27,54,376 परीक्षार्थी पंजीकृत है।इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे कुल 24,99,370 परीक्षार्थी- इसी तरह द्वितीय पाली (सायं 2-00 बजे से 5-15 बजे तक) इंटरमीडिएट की हिंदी एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा 7,998 परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न होगी जिसमें कुल 24,99,370 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड राज्य कंट्रोल रूम प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक विवेक नौटियाल के अनुसार, राज्य स्तरीय हाईटेक कंट्रोल रूम, लखनऊ से 75 जनपदों के सभी 8033 परीक्षा केंद्रों की लाइव ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत है। हाईस्कूल में 27,61,696 एवं इंटरमीडिएट 25,76,082 परीक्षार्थी शामिल होंगें। प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र स्थापित हैं। इनमें 596 राजकीय, 3453 सहायता प्राप्त एवं 3984 निजी विद्यालय शामिल हैं।

किसान हुंकार महापंचायतः भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भडके राकेश टिकैत, बोले-किसानों को बर्बाद करने पर तुली सरकार

किसान हुंकार महापंचायत में राकेश टिकैत ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है।यूपी के बहराइच में बुधवार को दरगाह इलाका स्थित गल्लामंडी परिसर में भारतीय किसान यूनियन की किसान हुंकार महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से देश में सब्सिडी और बिना टैरिफ के आने वाले समानों से देश के किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, इसे रोकने के लिए बड़ा आंदोलन करना होगा।मोहन भागवत ने बयान %हिंदुओं को तीन बच्चे करने चाहिए% पर टिकैत ने कहा कि हम तो जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग करते हैं। हम लोगों को एक बच्चे की ओर आना होगा, वरना आने वाले समय में स्थिति काफी खराब होगी। लेकिन, इन लोगों को जनसंख्या बढ़ाने में ही फायदा नजर आ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार सिर्फ हिंदू-मुस्लिम करती है। आज के समय में पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब हो चुके हैं। किसान नौजवान सभी परेशान हैं। ये लोग स्कूल न खोलकर सिर्फ शराब की दुकानें खोल रहे हैं।

इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम कुमार वर्मा, पयागपुर के पूर्व विधायक व सपा नेता मुकेश श्रीवास्तव, किसान नेता चंद्रशेखर सिंह आजाद, श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष अजीत चौधरी समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

संपादकीय Editorial

Debate in the Zero Room

The state, awaiting the droplets of debate in the Zero Room of the RDG, or revenue deficit grant from the center, is facing its own economic drought. We could even say that so and so is to blame for this situation. This was also a competition to see how to use the central relief. Politics, especially the BJP, has accepted that the Sukhu government is on a weak wicket, but this joy is laced with tears. We cannot view the state through two mirrors during this economic crisis, but in the void of the RDG, the think tanks of the BJP and Congress are becoming arenas for separate debates. In this context, Friday's all-party meeting was a sad day. At the very least, the next steps on this issue should be identified. These drums cannot be played alone. We are all guilty of the economic crisis. In this predicament, we are reminded of the wasteful expenditure in the name of development, and at least those speeches by governments, when, in a celebratory manner, they declared, "We will not let there be a shortage of funds." Now, the situation is such that the central government has stripped a hill state of its economic garb. In such a situation, is the central government doing justice by making the government run naked, or is this punishment waking us from our slumber? After all, such a massive structure didn't come up overnight. The past few decades have been marked by the exploits of various chief ministers. In Himachal, we have been squandering financial resources, burning budgets for political victory. Governments, driven by the idea of ??"Mission Repeat," bargained with the public, beyond the state's capacity, reality, and potential, and found neither Maya nor Ram in them. We have made the economy the fiefdom of chief ministers and considered financial methods a slave to boasting. Clearly, opportunities in Himachal have been squandered in the pursuit of economic resources. When Himachal Pradesh emerged from the princely state and was igniting the fire of Punjab reorganization, no effort was made to advocate for economic rights. In this confusion, we insulted the land that was divided from Punjab to Himachal. No one considered that Kangra's Haldoon Valley wasn't limited to the Pong displacement, but its agricultural productivity needed to be resettled elsewhere. We kept looking for central funds, unable to discern between the real and the real. Without understanding the criteria and financial structure of central schemes, this state kept accumulating the cement of progress, but failed to build an economic foundation. It's right to cultivate dreams of employment in education policy, but by making employment a government slogan, we have turned the realm of thinking into politics. When lamps are lit in praise of leaders in every aspect of life, on every public platform, and at the annual celebrations of educational institutions, politics has become the primary ideal for generations. While our leaders continue to effect transfers, electricity transformers continue to burn. If this weren't the case, why would any doctor, employee, or official consider themselves wealthy in the guise of a politician? Furthermore, political patronage would prevent government positions, swindling, the peddling of government files, and the exploitation of ordinary citizens' compulsions. Governments would come and go, and employee cadres would change. Empty coats would remain on secretariat chairs. In a state where ministers are solely focused on making their constituencies shine, departmental competence would only last five years. Himachal Pradesh has always operated on a five-year grace period, so the debts of outgoing governments have created new mountains of debt. The sips of Shimla's tea and coffee failed to notice the state's soil being eroded. Now, we can see the nurseries of politicians becoming wealthy through.

Challenges Ahead of Trade Agreements: Producing High-Quality Goods at Attractive Prices a Priority

To become an economic superpower, India is emphasizing trade agreements, which will increase access to global markets. However, agreements alone will not suffice. The country needs to produce quality products at attractive prices, increase investment in research and development, facilitate trade, and collaborate with states. Advances in emerging technologies like AI and quantum computing, and energy production for them, are crucial to achieving true economic power. Trade agreements are the first step to becoming an economic superpower. Investment in quality products and research and development is essential. Self-reliance in AI and energy production is a significant challenge. There is no country in the world that has become an economic superpower solely on the strength of self-reliance without trade. According to economic historian Angus Maddison, India also became an economic superpower on the strength of trade. Its economy grew to over a quarter of the world's economy, earning it the nickname "Golden Bird." In the modern era, every country from Britain to the United States has become an economic superpower solely on the strength of trade, and now China is on the same path. After establishing its dominance in the US and European markets, it began opening new markets for its goods through trade agreements even before the walls of protectionism were erected. The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) signed four years ago was a continuation of this, involving 15 countries ranging from China and Japan to New Zealand. Free trade agreements pave the way for increased mutual trade and the emergence of an economic superpower. India has also opened a similar path by signing an agreement with Europe and finalizing its framework with the US. Before the US and Europe, it has already signed trade agreements with ASEAN, Japan, the UK, Australia, South Korea, Singapore, Oman, Mauritius, and four members of the European Free Trade Association. Negotiations are underway for a trade agreement with the Gulf Cooperation Council. Upon completion, these agreements will open up markets representing over 60 percent of the world's GDP. This transformation is nothing short of a transformation for a country that has bankrupted its economy by 40 years of protectionism. It's also true that trade agreements and access to major markets alone cannot make a country a commercial and economic superpower. To achieve this, high-quality goods must be produced and sold at attractive prices. The shackles of license raj and bureaucracy must be eased to establish industries. Research, development, and innovation must be enhanced in both the public and private sectors, as well as areas where the country is ahead of others. Capital must be made accessible and infrastructure must be improved. These measures have allowed China to increase its trade to one and a half times India's GDP, even during Trump's tariff war. Today, India's share of world trade is only 3.5 percent, while China's is approximately 14 percent. During its heyday, India's share of world trade was around 30 percent. Recently, during British Prime Minister Keir Starmer's visit to China, a British bicycle manufacturer was asked where it was easier to do business between China and the United States. He promptly replied, "China, where business is possible within a few weeks and there is also certainty regarding trade policy." India too will need to instill similar confidence in businesses to attract large-scale foreign capital. This will be impossible without the active and positive participation of the states, along with the central government. Industries, in addition to capital, require land, workers, electricity, and infrastructure, all of which fall under the jurisdiction of states that, instead of competing with each other to attract investment, are often busy creating obstacles. Otherwise, why is Tirupur in Tamil Nadu capable of becoming the new Manchester of the garment industry, while Kolkata and Kanpur fail to regain their lost luster in the textile industry? Bengal has a population equal to Vietnam's, but its GDP is half that of Vietnam. Bihar has a one-and-a-quarter the population of Vietnam and a quarter of its GDP. What can you do in the race for development if you can't even match a country devastated by a 20-year war? Through trade agreements, India has opened the doors to the world's rich markets, such as the US, Europe, Japan, and Russia. However, to increase demand for its goods, it requires continuous improvement in quality and attractive prices. This will not be possible without expanding production and investing in research and development. China and Vietnam spend over 2.5 percent of their budgets on research and development, while India spends only 0.65 percent. In the wave of protectionism sparked by Trump's tariff war, self-reliance in the defense sector has become paramount, which is impossible without significant investment in research and development. To become an economic superpower, simply increasing trade will no longer suffice. India must also remain ahead in emerging technologies like AI and quantum computing, and the energy technologies required for these technologies. In the past few months, major US tech companies have pledged investments totaling approximately $80 billion to build AI data centers in India. These include names like Amazon, Microsoft, Google, and Intel. This is undoubtedly good news for the Indian economy, which has been struggling with declining foreign investment for the past few years. However, the massive energy requirements for these projects are beyond even Western developed nations. To build data centers and power-intensive AI models, India will need to increase its energy production to the scale of China, which currently produces two and a half times more electricity than the United States. Large-scale energy generation requires the development of clean energy sources like solar, wind, and hydrogen, ensuring the country's air remains breathable. The AI ??Impact Summit, which began in Delhi today, will address this issue, along with the need to make AI inclusive, people-friendly, and climate-friendly. This summit is expected to accelerate AI development, deployment, and investment in India.

MSMEs should become the foundation of a developed India and make them globally competitive.

The RBI has increased the collateral-free loan limit for micro and small enterprises from ?10 lakh to ?20 lakh, effective from April. This initiative will boost MSMEs, which contribute significantly to India's economy, manufacturing, and employment. Despite challenges, with the right policies and a focus on global competitiveness, MSMEs can strengthen the foundation of a 'developed India.' The RBI has increased the MSME loan limit from ?10 lakh to ?20 lakh. MSMEs are key pillars of India's economy and employment. Global competitiveness will help achieve the goal of a 'developed India.' The Reserve Bank of India (RBI) recently increased the limit for banks to provide collateral-free or collateral-free loans to micro and small enterprises (MSEs) from ?10 lakh to ?20 lakh. This decision will be effective for loans to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) from April this year. The 'Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises' will guarantee loans for entrepreneurs. This initiative by the RBI will undoubtedly prove to be an effective step in promoting MSMEs. It is worth noting that in this year's budget, the Finance Minister announced an increase in credit facilities for MSMEs and the creation of a separate fund of ?10,000 crore for them. The Economic Survey 2025-26 states that MSMEs strengthen India's industrial economy. This sector contributes approximately 35.4 percent of the country's total manufacturing output, approximately 48.58 percent of total exports, and approximately 31.1 percent of gross domestic product (GDP). Over 74.7 million enterprises in the country, employing approximately 328.2 million people, make this sector the second largest employer after agriculture. Globally, approximately 90 percent of businesses are in the MSME format and provide more than 50 percent of total global employment. As India's manufacturing sector moves towards global integration, the role of MSMEs is crucial in promoting effective supply chains, local value addition, and inclusive regional development. It is noteworthy that the Yashaswini Abhiyaan was launched on the occasion of "Entrepreneur India - MSME Day" in 2024, with the aim of promoting gender equality and ensuring a minimum three percent participation of women-owned MSMEs in public procurement by 2029. Last year, the Abhiyaan in Mizoram enabled the registration of approximately 8,400 women-owned MSMEs. To date, it has facilitated the registration of over 1.25 million women-owned MSMEs. The "Industrial Development Report 2024" published by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) lists India among emerging industrial economies. According to the report, the manufacturing sector in countries like India is expanding rapidly and industrial diversification is increasing. It also states that India has the potential to strengthen its participation in global value chains. Although the MSME sector has made significant progress, some structural challenges remain.

Issues such as delayed payments, lack of technological modernization, and limited global brand recognition continue to hamper the sector's momentum. While the number of registrations certainly paints a strong picture, there is a need to strengthen productivity per enterprise, quality standards, and global competitiveness. If these challenges are addressed through timely and effective policies, MSMEs can become a major pillar of a country's economic growth. The role of small and medium enterprises in the economic strength of South Korea and Japan is clearly visible. South Korea has provided small enterprises with research and development support, scale-up strategies, and legal protection through the Framework Act on Small and Medium Enterprises and the Ministry of Small, Medium Enterprises and Startups. On the other hand, Japan, under the Small and Medium Enterprise Basic Act, empowered its industries with a supply-chain-based "keiretsu" model, high quality standards, and technological innovation. The similarity between these two models is that they not only established a nurturing ecosystem for MSMEs, but also developed a structured system to elevate them to global competitiveness. If India similarly strengthens a clear scale-up policy and quality-oriented industrial coordination, MSMEs can further strengthen the foundation of a "developed India." In socio-economic development, MSMEs create substantial employment at low capital costs, support large industries as ancillary units, and promote industrialization in rural and backward areas. Therefore, India needs to provide long-term and affordable capital to MSMEs, encourage technological upgrading, and promote export-oriented brand building. Implementation of a timely payment mechanism and promotion of green production practices will also be essential. If MSMEs are given not just protection but a clear strategy to become globally competitive, they can become a crucial part of the economic structure of developed India. can be strengthened.

चांद नजर आया, मस्जिदों से किया गया ऐलान, शुरू हुआ मुकद्दस रमजान

ठाकुरद्वारा । मुकद्दस महीने रमजान का चांद नजर आने के साथ ही क्षेत्र में खुशी, रौनक और इबादत का माहौल बन गया है। चांद दिखाई देने की पुष्टि होने के बाद मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया कि

गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा। इसी के साथ एक माह तक चलने वाले रोजा, नमाज और इबादत के सिलसिले की शुरुआत होगी। बुधवार शाम को मगरिब की नमाज के बाद लोगों ने आसमान में चांद देखने की कोशिश की। चांद नजर आने की खबर मिलते ही मस्जिदों में तकबीरें गूंज उठीं। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। लोगों ने एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है, जिसे रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में रोजेदार सुबह सहरी के समय भोजन कर रोजा शुरू करते हैं और सूर्यास्त के समय इफ्तार कर रोजा खोलते हैं। दिनभर भूखे-प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत की जाती है और बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लिया जाता है। उलेमा-ए-कराम ने बताया कि रमजान आत्मशुद्धि, संयम और सामाजिक एकता का संदेश देता है। इस महीने में जकात और फितरा अदा कर जरूरतमंदों की मदद करने का विशेष महत्व है। रमजान को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। खजूर, फल, सेवईं, सूखे मेवे और अन्य खाद्य सामग्री की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। सहरी और इफ्तार की तैयारियों में परिवार जुट गए हैं। उलेमाओं ने अपील की है कि रमजान के पाक महीने में इबादत के साथ-साथ आपसी भाईचारा, अमन-चैन और सद्भाव बनाए रखें। साथ ही स्वच्छता, संयम और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए इस पवित्र माह का सम्मान करें। रमजान माह की शुरुआत को लेकर रोजेदार तैयारी में जुट गए हैं। मस्जिदों में जहां तैयारी की जा रही है वहीं बाजार में इसके लिए खरीदारी बढ़ गई है। शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने बताया कि बुधवार को चांद दिखने की उम्मीद है। यदि बुधवार की शाम चांद नजर आ जाता है तो जुमेरात को पहला रोजा रखा जाएगा। वहीं, अगर जुमेरात की रात चांद दिखाई देता है तो शुक्रवार को पहला रोजा रखा जाएगा। चांद के दीदार के बाद औपचारिक रूप से रमजान की शुरुआत का ऐलान किया जाएगा।उन्होंने बताया कि रमजान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें रोजेदार सुबह सहरी के समय भोजन करने के बाद दिनभर रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं। इस महीने में इबादत, तिलावत-ए-कुरान, तरावीह की नमाज और जरूरतमंदों को दान का विशेष महत्व होता है। मस्जिदों में साफ-सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इधर, बाजारों में भी रमजान की तैयारियों को लेकर भीड़ बढ़ गई है। लोग खजूर, सेवइयां, फलों और इफ्तार से जुड़ी अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी में जुटे हैं। इसके अलावा नए कपड़े, टोपी, इत्र और नमाज से संबंधित सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि रमजान के चलते बिक्री में तेजी आई है और आने वाले दिनों में और अधिक रौनक की उम्मीद है।

उमंग और उत्साह के साथ केंद्रों पर पहुंचे छात्र-छात्राएं, हिंदी के पेपर से शुरुआत..

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटर परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो गई। मुरादाबाद में 112 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इस दौरान छात्र उत्साहित दिखे।मुरादाबाद में कड़ी निगरानी के बीच बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया। सुबह आठ बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की भीड़ नजर आने लगी। प्रथम पाली में हाईस्कूल की परीक्षा सुबह साढ़े आठ बजे हिंदी प्रश्नपत्र के साथ शुरू हुई। केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा।जिले में बनाए गए सभी केंद्रों पर मंगलवार से ही सीटिंग प्लान और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई थीं। परीक्षा शुरू होते ही कंट्रोल रूम से

ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी गई। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।मुरादाबाद में इस बार 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 19 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। हाईस्कूल में 39,560 और इंटरमीडिएट में 36,200 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। 15 दिन तक चलने वाली इन परीक्षाओं में कुल 75,760 परीक्षार्थी शामिल होंगे।माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से निगरानी के लिए पांच जोनल मजिस्ट्रेट, छह सचल दल, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, दस रात्रिकालीन निगरानी दल, 112 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 112 केंद्र एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, एक संकलन केंद्र और तीन उप संकलन केंद्र बनाए गए हैं।जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय के अनुसार प्रश्नपत्रों से छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए दस रात्रिकालीन सचल दल गठित किए गए हैं। वह रात में भ्रमण कर केंद्रों के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करेंगे। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी।

चचेरे मामा ने की भांजे की हत्या, सिर में घुसा मिला धारदार हथियार; अवैध संबंधों में बन रहा था बाधा

रामपुर में अवैध संबंधों में बाधा बनने पर चचेरे मामा ने भांजे की दरांती से हमला कर हत्या कर दी। चीख सुनकर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार में अवैध संबंधों में बाधक बने चचेरे मामा ने भांजे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार, कोतवाली इलाके के मसवासी पुलिस चौकी के खौदकलां गांव में मंगलवार की रात लगभग पौने 12 बजे कथित अवैध संबंधों में बाधक बने चचेरे मामा ने भांजे मोहम्मद आकिल (28) की दरांती के प्रहार से हत्या कर दी। चीख निकलने पर पड़ोसी ने आरोपी को भागते हुए देखा। मौके पर तमाम ग्रामीण इकठ्ठा हो गए। सूचना पर कोतवाल संजीव कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। खौदकलां गांव के लोग मंगलवार की रात गहरी नींद में सो रहे थे तभी उन्होंने चीखों की आवाज सुनी। लोग घरों से बाहर निकल आए और वह मोहम्मद आकिल के घर पहुंचे तो वो रक्तरंजित अवस्था में मिला। उसके सिर में दरांती घुसी हुई थी। घटना के समय वह घर में अकेला था। सूचना मिलने पर कोतवाली और मसवासी चौकी पुलिस आ गई। पुलिस को आकिल मृत अवस्था में में मिला। इसके चलते शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। घर में अकेला रहता था आकिल - आकिल के माता-पिता का काफी साल पहले निधन हो चुका है। एक बहन थी वह भी शादी के बाद अपनी ससुराल में रह रही है। आकिल की शादी हो चुकी है लेकिन पत्नी शाइस्ता लगभग छह माह पहले उसे छोड़ तीन बच्चों को लेकर अपने मायके जाकर रहने लगी है। आरोप है कि आकिल को नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों से नाराज होकर वह पहले भी कई बार पति को अकेला छोड़ कर मायके जा चुकी है। इस तरह अकील अपने घर में अकेला ही रह रहा था। चचेरे मामा पर हत्या का आरोप- गांव में उसके चचेरे मामा नसीम उर्फ भूरा रहता है। उसकी शादी हुई थी लेकिन पत्नी तलाक लेकर उसे छोड़ गई। बताते हैं कि भांजा मोहम्मद आकिल अपनी पत्नी को घर लाना चाहता था लेकिन वह आने को तैयार नहीं थी। बताते हैं कि वह ममेरे ससुर नसीम उर्फ भूरा के सांपर्क में थी। नसीम से मोबाइल पर बात करती थी। चर्चा है कि मोहम्मद आकिल को रास्ते से हटाकर वह उसकी पत्नी को खुद अपनी पत्नी बनाना चाहता था। संभव है कि इसी कारण मंगलवार की रात मोहम्मद आकिल की जघन्य हत्या कर दी गई। चचेरा मामा पुलिस की हिरासत में- चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने देखा कि नसीम उर्फ भूरा, मोहम्मद आकिल के घर से भागने का प्रयास कर रहा था। भीड़ जमा होने के कारण वह भाग नहीं सका। इसी दौरान कुछ देर में पुलिस आ गई और उसे कब्जे में ले लिया गया। आकिल का है आपराधिक इतिहास- पुलिस और ग्रामीणों के मुटाविक आकिल का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। उसके खिलाफ थाना टांडा के अलावा उत्तराखंड के रुद्रपुर और हल्द्वानी में चोरी के कई मुकदमे दर्ज हुए। वह कई बार जेल भी जा चुका था। इसके आलावा वह नशा भी करने लगा। शाइस्ता पति की इन हरकतों से तंग रहती ही और उसे छोड़कर अपने तीन बच्चों के मायके में रहने लगी।

संक्षिप्त समाचार

पुलिस ने विधानसभा घेराव को निकले कांग्रेसियों को किया हाउस अरेस्ट

विधानसभा सभा घेराव के लिये युवा कांग्रेस रामपुर के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह 4 बजे काजी गली स्थित युवा कांग्रेस के कैंप कार्यालय में एकत्रित हुए। इसी दौरान पुलिस ने

सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया। कार्यकर्ताओं ने कूच करने की कोशिश की उन्हें गाड़ियों में भर लिया और पुलिस चौकी ले जाकर बैठा लिया। हालांकि दोपहर करीब दो बजे पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। युवा कांग्रेस के महासचिव अरसलान खां ने इसे सरकार की दमनकारी नीति बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस से डरने वाली नहीं, यह सीधा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। मनरेगा रोजगार की गारंटी है, जिस के नियमों को कांग्रेस बदलने नहीं देगी और हर स्तर पर इसमें बदलाव का विरोध करेगी।जिला अध्यक्ष मो. आरिफ ने इसे संविधान विपरीत लोकतंत्र की आवाज को दबाने का असफल प्रयास है। कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिये डटा रहेगा। शहर विधान सभा अध्यक्ष यासिर शाह खां ने सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए मोहब्बत के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने और दमनकारी नीतियों का डट कर मुकाबला करने का संकल्प दोहराया।

स्वार में नकली कैल्शियम बेचते हुए पकड़ा गया दुकानदार

क्षेत्र में किसानों के शोषण का एक और मामला सामने आया है। फसल की पैदावार बढ़ाने के नाम पर किसानों को नकली खाद और दवाइयां बेची जा रही हैं। जिससे वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। मंगलवार को नकली

कैल्शियम बेचने की सूचना पर गुड़गांव से आई कंपनी टीम ने नगर के मुख्य चौराहे के निकट स्थित शर्मा फर्टिलाइजर की दुकान पर छापामार कार्रवाई कर एक नकली कैल्शियम का कट्टा बरामद किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकानदार को यारा वीरा नाइट्रोजन कैल्शियम का नकली कट्टा 500 रुपये में बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जबकि बाजार में इसी कंपनी के असली कैल्शियम कट्टे की कीमत लगभग 1400 रुपये बताई जा रही है। सस्ते दामों का लालच देकर किसानों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी की जा रही थी। छापेमारी करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे एरिया मैनेजर धर्मेंद्र कुमार ने तत्काल इसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह को दी। सूचना मिलते ही जिला कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने टीम को नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने कैल्शियम के नमूने लेकर लैब को भेजा है। कार्रवाई के दौरान नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के खाद बीज विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा। गौरतलब है कि क्षेत्र में लंबे समय से नकली खाद एवं कीटनाशक और कृषि दवाओं का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, जहां मेहनत की कमाई लूटने के साथ साथ फसलें भी खराब हो रही हैं।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी, डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991

RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

किसान दिवस विकास भवन सभागार में हुआ समापन

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली । विकास भवन सभागार में उप कृषि निदेशक, की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। उप कृषि निदेशक, महोदय द्वारा सम्बोधन संचालन की शुरूआत की गयी तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विगत माह के किसान दिवसों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में बिन्दुवार अवगत कराया गया। क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक शिकायत के निस्तारण को सुना गया जिसमें सर्वप्रथम कृषक प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन(शंकर), द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम रहटुईया तहसील ऑवला के द्वारा मनरेगा, विद्युत विभाग, ग्राम प्रधान एवं पी.डब्लू.डी. विभाग द्वारा सड़क निर्माण जोकि ग्रामीण क्षेत्र से होकर जा रही है जिस पर राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश कराकर अतिक्रमण हटवाया जाये। कृषक एम.पी. सिंह द्वारा विद्युत विभाग का समस्या को बताया गया, ग्रामीण क्षेत्र ग्राम खनगवां श्याम मे बिना मीटर के रू. 600 का बिल आया है। शिवकुमार शर्मा, समाजसेवी बहेड़ी द्वारा नगरपालिका बहेड़ी की अधिशासी अधिकारी द्वारा गैर जिम्मेदारी के बारे में अध्यक्ष महोदय को शोशण के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया, जिला कृषि अधिकारी, महोदया, के सम्बोधन उपरान्त धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किसान दिवस के समापन की घोषणा की गयी। इस अवसर पर बरेली के प्रगतिशील कृषकों एवं कृषि विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, उद्यान विभाग, नलकूप विभाग, गन्ना विभाग तथा अन्य समबद्ध विभाग के अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

घरेलू कलह में मां को चाकू मारकर उतारा था मौत के घाट , अब हुई उम्रकैद की सजा

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। घरेलू कलह में मां की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी थाना किला के पंजाबपुरा साहूकारा निवासी सूरज को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 अमृत शुक्ला की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। वादी बाबूराम ने थाना किला में तहरीर देकर बताया कि 18 अक्टूबर 2022 को करीब 3.30 बजे भांजे सूरज ने घरेलू कलह को लेकर अपनी मां मंजू देवी को चाकू मारकर घायल कर दिया व मंजू को बचाने आयी अपनी पत्नी अनीता देवी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त मंजू की रास्ते में ही मौत हो गयी। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 14 गवाह पेश किये थे।

फीस जमा न करने पर तीन छात्रों के प्रवेश पत्र रोके, निजी स्कूल में हंगामा

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। सुभाष नगर क्षेत्र में रामगंगा के समीप स्थित सेंट एंड्रू स्कूल ने फीस बकाया होने के चलते 12वीं कक्षा के तीन छात्रों के प्रवेश पत्र रोक लिए। बुधवार सुबह जब सीबीएसई 12वीं की परीक्षा शुरू हुई तो तीनों छात्र स्कूल प्रबंधन के चक्कर काटते रहे। फीस जमा न होने का हवाला देकर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें एडमिट कार्ड देने से साफ इनकार कर दिया। इसके कारण ये छात्र फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा नहीं दे सके। मामले की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पदाधिकारी स्कूल पहुंच गए। प्रांत मंत्री आनंद कठेरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रिंसिपल कार्यालय में ताला जड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सीबीएसई की सिटी कॉर्डिनेटर ममता सक्सेना ने स्पष्ट किया , कि %सेंट एंड्रू स्कूल% नाम का कोई भी संस्थान सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं, स्कूल के प्रबंधक मोहित चंद्र का कहना है कि यह एक कोचिंग सेंटर है और अभिभावकों को बुलाने के लिए ही एडमिट कार्ड रोके गए थे।

बरेली में वृध्दाश्रम जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष/वरिष्ठ न्यायामूर्ति, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त आम जनता के विधिक सशक्तीकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा दिनांक 22.02.2026 को मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन जी.आई.सी. ऑडिटोरियम, बरेली में किया जा रहा है। बरेली न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, निर्देशानुसार उक्त मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के सफल आयोजन के सम्बन्ध में पुन: प्री-शिविर का आयोजन वृध्दाश्रम, लाल फाटक, बरेली में किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.02.2026 को आयोजित मेगा शिविर में समस्त विभागों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जो अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित समस्याओ का निस्तारण करेंगे एवं जरुरतमन्द व्यक्तियों का पंजीकरण करेगे। उक्त शिविर जागरुकता शिविर में जिला चिकित्सालय से चिकित्सकों की एक टीम द्वारा प्रतिभाग कर वृध्दाश्रम बरेली में निवासरत वृध्दों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच की गयी तथा दवाओं का निशुल्क वितरण किया गया ।

बरेली जंक्शन से करोड़ों की बैटरी चोरी, 142 कोच से 1200 बैटरी के मामले ने पकड़ा तूल

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन की वॉशिंग लाइन और स्टोर से अलग - अलग ट्रेनों के 142 कोचों की 1200 से अधिक बैटरियां गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है। यह मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल मुख्यालय में खलबली मच गई। बताया जाता है कि मंडल मुख्यालय में स्टोर इंचार्ज समेत कई अधिकारियों की पेशी हुई और विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, इस मामले में इंस्पेक्टर आरपीएफ से जानकारी की कोशिश की। मगर, उनका फोन नहीं उठा। बरेली जंक्शन पर 135 बैट्री गायब होने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक, जंक्शन के पूर्वी आउटर स्थित वॉशिंग लाइन में ट्रेनों के कोचों की मरम्मत और तकनीकी देखभाल की जाती है। उसके पास में ही स्टोर है, जहां पुरानी बैटरियां और अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री रखी जाती है। हाल ही में स्टॉक का मिलान किया गया, तो 142 कोचों से 1200 से अधिक बैटरियां गायब मिलीं। बैटरियों की बाजार कीमत काफी अधिक बताई जा रही है, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से बैटरियां और स्क्रैप गायब होता रहा, लेकिन किसी स्तर पर गंभीर निगरानी नहीं की गई। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) आदित्य गुप्ता ने मीडिया को बताया कि विभागीय जांच जारी है। जांच पूरी होने से पहले बैटरियों की सटीक संख्या और नुकसान का अंतिम आकलन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सांड़ ने मचाया आतंक, हमले में किसान की हुई मौत, महिला समेत हुए चार घायल

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक सांड़ ने आतंक मचाया। सांड़ ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे गांव बभिया निवासी किसान रामफेर पाराशर की मौत हो गई। जबकि चार ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने सांड़ को पकड़वाने की मांग की है। गांव बभिया निवासी मुनेंद्र ने बताया कि उनके चाचा रामफेर पाराशर अविवाहित थे। वह बुधवार सुबह ग्रामीणों के साथ खेत पर जा रहे थे। रास्ते में सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। उनको सींगों से उठाकर पटक दिया। ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया तो सांड़ ने उन लोगों पर भी हमला कर दिया। घटना से मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। किसी तरह सांड़ को वहां से भगाया। इलाके में छुट्टा पशुओं का है आतंक - इसके बाद घायलों को आनन-फानन अस्पताल पहुंचाया गया। जहां रामफेर पाराशर को मृत घोषित कर दिया गया। सांड़ के हमले में गांव के ही उदयवीर, विद्यावती, अशोक शर्मा और उनका बेटा अमित घायल हुए हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। मुनेंद्र ने बताया कि इलाके में बहुत छुट्टा पशु हैं, लेकिन यह सांड़ मंगलवार को कोई यहां छोड़कर गया था। उन्होंने हमलावर सांड़ को जल्द पकड़वाने की मांग की है। गांव के प्रधान ने बताया कि गांव में कोई गौशाला नहीं है। शहर से पकड़े जाने वाले छुट्टा पशुओं को गांव में छोड़ दिया जाता है। इस सांड़ को भी कोई छोड़ गया था। कैंट थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि किसान के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है।

दूसरे राज्य में की पढ़ाई अब जिले का बनना है मतदाता, एसआईआर में अंकपत्रों की हो रही जांच

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वोट बनवाने के लिए उन महिला -पुरुषों को दिक्कतें आ रहीं हैं, जिन्होंने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 30 से लेकर 50 साल की उम्र में ने जन्मतिथि के लिए मार्कशीट की कॉपी लगाई और संबंधित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से जांच कहीं कोई गड़बड़ या फर्जीवाड़ा तो नहीं किया बरेली के कई स्कूलों से पढ़ाई की है, लेकिन के साथ बरेली में रहने के दौरान हाईस्कूल और मूल पते पर निवास कर रहे हैं। डीएम के निर्देश अंकपत्रों की जांच करायी है। दरअसल, फरवरी को डीआईओएस को पत्र लिखा गया। दूसरे राज्य के विभिन्न जनपदों के स्कूलों से वोट बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों है। अब उनकी मार्कशीट की संबंधित स्कूलों करायी जा रही है। यह देखा जा रहा है कि गया। ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं, जिन्होंने मूलतः रहने वाले विभिन्न प्रदेशों के हैं। परिवार इंटरमीडिएट पास किया, लेकिन अब अपने पर डीआईओएस ने बरेली में पांच स्कूलों में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की ओर से 11 उसी पत्र के अनुपालन में डीआईओएस डॉ. अजीत कुमार ने शहर के महावीर प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज, श्री गुरुनानक रिक्खी सिंह कन्या इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और फतेहगंज पश्चिमी के एसटीके हायर सेकेंड्री स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। उस पत्र के साथ इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अंक पत्र और सह प्रमाणपत्र की सूची सत्यापन के लिए भेजी। सभी को निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। ये कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अंकपत्र व सह प्रमाणपत्रों का सत्यापन एवं संबंधितों की जन्मतिथि का भी सत्यापन किया जाना है। इसके बाद प्रधानाचार्यों ने अपने स्कूलों में अंकपत्रों की जांच करायी। इसके साथ अंकपत्रों की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद के बरेली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से भी करायी गयी। इधर, डीआईओएस डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि कुछ स्कूलों से संबंधित अंकपत्र जांच के लिए आए थे, जांच कराकर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गयी है।

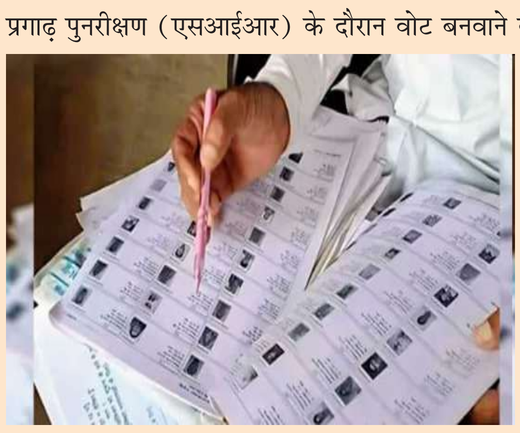

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए - 9027776991

संक्षिप्त समाचार

जिला अधिकारी ने 10 से 12 बजे के दौरान जनता दर्शन में सुनी जनसमस्याएं

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / सम्बंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिए निर्देश बरेली, । जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने प्रत्येक दिवस की भांति कलेक्ट्रट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान जन सामान्य की समस्याओं को बारी बारी सुना और प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आदेश दिए। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को समस्त सम्बंधित अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आमजन की समस्याओं को सुनकर शत प्रतिशत उनका निराकरण किया जाये। जनसुनवाई के दौरान कहा कि जमीन से संबंधित समस्या को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर निस्तारण कराएं। जिला अधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान जो भी शिकायतें आ रही है उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ससमय सुनिश्चित कराएं और शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट होना चाहिए ।

एसबीआई ने प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प कराया , छात्र व छात्राओं को बांटी स्टेशनरी

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली । प्राथमिक विद्यालय आसपुर खूबचंद में बुधवार को विशेष उत्सव का माहौल बना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विद्यालय का कायाकल्प करवाया गया । एवं छात्र -छात्राओं को स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर, शौचालय इंटरलाकिग,के साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र -छात्राओं को स्कूली बैग कापी पेंसिल, पानी की बोतल आदि वितरित की गई। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज कुमार राय,अलका शर्मा शाखा प्रबंधक,महानगर सौरभ त्रिवेदी प्रबंधक मानव संसाधन वर्षा कसेरा उप प्रबंधक, प्रधान उमंग कौशिक शिक्षिका विनीता रस्तोगी, शिक्षामित्र गायत्री यादव, सहित तमाम अभिभावक मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी बिथरी चैनपुर विजय कुमार सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक का आभार प्रकट किया ।

बरेली के सीबीगंज में सुपीरियर शराब फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। मंगलवार की देर शाम 8 बजे से लखनऊ और दिल्ली की कई टीमें फैक्ट्री में माल खरीदने और बेचने के कागजात खंगाल रही हैं, सभी कर्मचारियों के मोबाइल स्विच ऑफ करके जमा कर लिए हैं, फैक्ट्री के अंदर बाहर किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई है, बड़ी संख्या में कर्मचारी अंदर हैं, बाहर कड़ा पहरा है, कई गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, सुपीरियर शराब फैक्ट्री में छापा मारने पहुंची हैं। मंगलवार की देर शाम 8 बजे से टीम सुपीरियर शराब फैक्ट्री में पहुंच गई, दिल्ली लखनऊ की बताई जा रही है, शाम से फैक्ट्री में ही कर्मचारियों को रोके रखा है।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

9027776991

knlslive@gmail.com

यूपी बजट सत्र: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब

यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। प्रश्नकाल में प्रदेश में बिजली आपूर्ति और मुफ्त बिजली देने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया जिस पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जवाब दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में तकरार भी हुई।विधान परिषद्- बिजली वॉक आउट किया बिजली के निजीकरण से वॉक आउट किया। श्रम मंत्री अनिल नौकरियां मिलीं हैं उससे कई गुना ज्यादा अहिल्याबाई के अपमान को लेकर उठाए साहस की प्रतिमूर्ति हैं। उनका नाम कभी कोई अपमान कर सकता है। भाजपा सरकार है। ऐसी बातें वो ही कह रहे हैं जिनकी खुद निर्णय लेगी सरकार- यूपी के बेसिक शिक्षा मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और कि बेसिक शिक्षा विभाग के लिए शिक्षामित्रों की ग्राम पंचायतों में तैनाती को लेकर कहा जारी है जिसमें शिक्षामित्र अपना दायित्व होते ही उनकी ग्राम पंचायतों में तैनाती हो आदेश जारी कर दिया है। वहीं, शिक्षामित्रों, तक के कैशलेस इलाज की मांग को भी

के निजीकरण के मुद्दे पर सपा सदस्यों ने के मुद्दे पर सपा सदस्यों ने विधान परिषद राजभर ने कहा कि सपा सरकार में जितनी नौकरियां दीं।विधायक पूजा पाल ने राजमाता जा रहे विपक्ष के आरोपों पर कहा कि वो कोई नहीं मिटा सकता है और न ही कभी उनके सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध की मंशा खराब है।शिक्षामित्रों के हित में मंत्री संदीप सिंह ने सदन में शिक्षामित्रों के ग्राम पंचायत में तैनाती के संबंध में कहा की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षामित्रों कि अभी प्रदेश में एसआईआर का काम निभा रहे हैं। एसआईआर का काम पूरा जाएगी। इस संबंध में हमारी सरकार ने शिक्षकों और अनुदेशकों को पांच लाख सरकार ने मंजूर कर लिया है। वहीं, शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो 2012 से 17 तक शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। जब हमारी सरकारी आई तो उनका मानदेय 3500 रुपये था जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया। शिक्षामित्रों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील हैं। सरकार आगे भी शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेगी।वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि खादी आश्रम की जमीन को सपा सरकार में कुछ लोगों को समझौते के तहत दिया गया था जिसे अब सरकार ने अपने पक्ष में अधिग्रहीत करने का मन बनाया है। मामले में लीगल ओपीनियन ली जा रही है जिन लोगों को जमीन दी गई थी उन्होंने कॉलेज बनाने की बात की थी पर नहीं बनाया। अब सरकार अपने पक्ष में जमीन अधिग्रहीत करने के लिए काम कर रही है।यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मेरठ में गांधी आश्रम की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर लगातार कब्जे की कोशिश की जा रही है। जो कि हमारे पूर्वजों के खून-पसीने की है। इस पर चर्चा की जाए जिससे कि वस्तुस्थिति सामने आ सके।ऊर्जा मंत्री के जवाब पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने नाराजगी जताई और कहा कि वो असत्य बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि सपा सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। वो अधिक बोल रहे हैं। हमने कोई पाप नहीं किया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जी ऐसा नहीं कहा कि सपा सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 2017 से पहले क्या काम हुआ था और 2017 के बाद क्या-क्या हुआ।प्रश्नकाल में सपा नेता डॉ. रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल को देगी? इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल हमारे लिए संवेदनशील विषय हैं। सरकार इन वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य, बिजली और अन्य कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध करवा रही है। ऐसे लोगों की संख्या राज्य में करीब 3 करोड़ 72 लाख है जिन्हें कम दाम पर मुफ्त बिजली दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री के जवाब पर सपा नेता शिवपाल सिंह ने नाराजगी जताई और कहा कि मंत्री असत्य बोलते हैं कि 2017 के पहले कुछ काम ही नहीं हुआ है।यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सपा नेता व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच किसानों को मुफ्त बिजली देने पर तकरार हो गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले किसानों को 10 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए थे। हमने सिर्फ नौ वर्षों में आठ लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए और किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं जारी करने के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया- सपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में एसआईआर में गड़बड़ी और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं जारी करने के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि उनकी बातचीत में एसडीएम ने स्वीकार किया है कि उसे प्रमाणपत्र जारी करने से मना किया गया है।यूपी बजट सत्र- शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया ये जवाब- यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। बुधवार को यूपी में हो रहे एसआईआर सहित कई मुद्दों विपक्षी दल उठा सकते हैं। इसके मंगलवार को सपा सदस्यों ने एसआईआर और जन्म प्रमाण पत्र के मुद्दे पर सदन से बर्हिगमन किया था।

भारत-यूरोप के विश्वास और वैश्विक कार्यबल का सेतु, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस की शुरुआत पर जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस को भारत और यूरोप के समाजों के बीच सेतु और वैश्विक, कुशल कार्यबल में निवेश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव, तकनीक और जनसांख्यिकी के दौर में अवसरों को जोड़ने लॉन्च पर बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े कम करना अब एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है, करने के तरीके बदल दिए हैं। दुनिया के अलग- और अब वैश्विक कार्यबल का विचार तेजी से प्रवाह को अवसरों के साथ जोड़ सकें और इसमें का सबसे अच्छा फायदा उठा पाएंगे। उन्होंने एआई क्षमता को समझना था, जो सामाजिक और आर्थिक और बड़े स्तर पर समाधान दे सकती है।जयशंकर ने यूरोप के लिए भारत का यूरोपीय लीगल गेटवे यह सिर्फ यूरोप में प्रवेश का जरिया नहीं है, बल्कि एक साझा, कुशल, गतिशील और मजबूत वैश्विक इसके साथ ही विदेश मंत्री ने भारत-यूरोपियन हमारी साझेदारी सिर्फ साझा मूल्यों की वजह से ही

में मदद करेगा।भारत में यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस के दोनों देशों के संबंध समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने बताया कि जोखिम सप्लाई चेन का ढांचा बदला जा रहा है और तकनीक ने काम अलग हिस्सों में जनसांख्यिकी में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं सामने आ रहा है।जयशंकर ने कहा कि ऐसे देश जो प्रतिभा के कानून, पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखें, वे इस बदलाव इम्पैक्ट समिट के बारे में कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य एआई की विकास को बढ़ा सकती है और विभाजन को कम कर सकती है ने यूरोपीय लीगल गेटवे का दिया उदाहरण- इस दौरान जयशंकर ऑफिस भी इसके उदाहरण के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाजों के बीच एक सेतु है, विश्वास का प्रतीक है और कार्यबल में निवेश है। भारत यूरोप साझेदारी का भी जिक्र- यूनियन (ईयू) साझेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि इसलिए भी मजबूत है क्योंकि अब हम एक-दूसरे को प्राकृतिक और पसंदीदा साझेदार के रूप में देखते हैं।उन्होंने कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत का निष्कर्ष, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर समझौता और 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के अन्य ठोस निर्णय हमारे साझा भविष्य का रोडमैप पेश करते हैं। जयशंकर ने बताया कि शिखर सम्मेलन में 2030 तक की संयुक्त रणनीतिक एजेंडा को अपनाना हमारे रिश्तों का एक नया अध्याय खोलता है, जो आपसी समृद्धि, सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है।

भुता क्षेत्र के सहोद्रा देवी स्कूल का फर्जीवाड़ा फीस लेने के बाद भी 10 बी और 12 बी की छात्राओं को नहीं दिए प्रवेश पत्र

क्यूँ न लिखूँ सच/ भुता । क्षेत्र के सहोद्रा देवी स्कूल में बहुत बड़े फर्जीबाड़े का खुलासा हुआ है। जिसकी वजह से यूपी बोर्ड की लगभग आधा दर्जन से अधिक छात्राओं का भविष्य अंधेरे में धकेल

दिया गया ।स्कूल प्रबंधन ने पूरी फीस लेने के बाद भी छात्राओं को नहीं दिए प्रवेश पत्र जिसकी वजह से छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गई। क्षेत्र के गांव गंगापुर डबोरा में स्थित सहोदरा देवी मेमोरियल कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल/ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार ने लगभग आधा दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ धोखाधड़ी करके उनका भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। प्रधानाचार्य कमलेश कुमार पर आरोप है कि दसवीं की छात्राओं से 4500 रुपए और इंटर की छात्रों से 7200 वसूल किए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज 18 फरवरी से शुरू हो गई है। छात्र जब अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए विद्यालय जाती थी तब प्रधानाचार्य कमलेश कुमार टाल मटोल कर देता था। आज परीक्षा शुरू होने से पहले कक्षा 12 की छात्राएं नेहा प्रियंका ,नैंसी, और कक्षा 10 की छात्राएं चांदनी , ,,कुसुम, मोहिनी खुशी, आदि छात्राएं अपने अभिभावकों को लेकर स्कूल पहुंची । अभिभावकों ने प्रधानाचार्य कमलेश कुमार से प्रवेश पत्र देने को कहा तभी वह गाली गलौज करने लगा। अभिभावकों का आरोप है कि कमलेश कुमार ने धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। मजबूरन सभी छात्राओं ने भुता पुलिस को लिखित तहरीर दी है पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है । ज्ञात रहे इस स्कूल में हर वर्ष कुछ ना कुछ छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह जाती है। जानकारी पर पता चलता है कि प्रधानाचार्य कमलेश कुमार उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता है और पूरी साल धोखाधड़ी से फीस लेता रहता है। थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है प्रधानाचार्य कमलेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है जांच पड़ताल कर अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है।

संक्षिप्त समाचार

कड़ी सुरक्षा के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा बुधवार से हुई शुरू

रामपुर जिले में 74 परीक्षा केंद्रों पर बुधवार आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े

बंदोबस्त किए गए हैं। उड़ाका दल, पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरों के अलावा 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 74 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 74 परीक्षा केंद्रों पर 46,766 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 25,518 छात्र पंजीकृत हैं। रजा इंटर कालेज में बनाए गए कंट्रोल रूम में लखनऊ से मॉनिटिरिंग हो रही ही। कंट्रोल रूम में 21 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे परीक्षा कक्ष में पैनी नजर रखी जा रही है। नकलविहीन परीक्षा कराए जाने के लिए वायस रिकार्डर लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर साफ पानी, बिजली, शौचालय, जेनरेटर की भी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों के लॉकर में रखवा दिए गए हैं। लॉकर की एक चॉबी केंद्र व्यवस्थापक और एक चाबी वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। इसके अलावा लॉकर पर 24 घंटे कैमरे नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा। 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 74 स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा पर नजर बनाए रहेंगे। कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों के दो-दो सेट भेजे गए हैं। हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या - 25,518 इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या- 21248 कुल परीक्षार्थियों की संख्या - 46,766

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की योगी से मुलाकात, लखनऊ का दो दिवसीय दौरा, इस बात पर दिखा फोकस

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों के तहत सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। भागवत ने मंदिर, कुआं और श्मशान सभी हिंदुओं के लिए बिना भेदभाव खुले रखने का आह्वान किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की। आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला में मोहन भागवत लखनऊ के दो दिवसीय काफी अहम माना जा रहा है। संघ प्रमुख ने अपने यूपी प्रवास के दौरान संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस कर रखा है।इससे पहले आज सुबह दो दिवसीय प्रवास के दौरान अंतिम दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ की सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज ही है क्योंकि हमें उन्हें जगाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है।दिलीप कुमार ने सवाल किया कि भाजपा की सरकार बनते ही कुछ अवसरवादी लोग अपने फायदे के लिए संघ में शामिल हो जाते हैं जिससे समर्पित कार्यकर्ता भी उदासीन हो जाते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपने समर्पण की जांच करानी चाहिए। संघ की कार्यपद्धति फूलप्रूफ है क्योंकि संघ देश के उत्थान के लिए समर्पित कार्यकर्ता से केवल लेता ही है, उसे देता कुछ नहीं। अगर अवसरवादी लोग आ भी जाते हैं तो वे संघ में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मंदिरों के धन का प्रयोग जनसेवा के लिए भक्तों को ही करना चाहिए डॉ. श्वेता श्रीवास्तव और कर्नल एमके सिंह के एक सवाल के जवाब में डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि मंदिरों से होने वाली आय को जन कल्याण के लिए लगाना चाहिए और इसकी बागडोर सरकार के हाथों में न होकर जिम्मेदार भक्तों के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख मंदिरों के संचालन और आय के जन कल्याण के लिए खर्च किए जाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और निष्पक्ष व ईमानदार संस्था की निगरानी में हो। उन्होंने कहा कि संघ इस दिशा में आगे तैयारी कर रहा है, जल्द परिणाम देखने को मिलेगा। टैरिफ वार को दिल पर न लीजिए- मुख्यमंत्री के सलाहकार व पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी के प्रश्न के जवाब में डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि टैरिफ वार को दिल पर न लीजिए। सामने वाला हमें दबाकर देख रहा है कि हम कितना दब सकते हैं लेकिन उन्हें पता है कि हम दबेंगे नहीं। कहा, व्यापार विश्वास पर ही चलता है और टैरिफ की जबरदस्ती करने वाले अपना विश्वास खो रहे हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा विश्वास मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाई मास पर है।

पोहरी एवं करेरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु बजट में 322 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

क्यूँ न लिखूँ सच/ राजकुमार शर्मा (कटारे)/ शिवपुरी, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह के प्रयासों से मध्यप्रदेश के बजट में ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पोहरी एवं करेरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 322 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद श्री कुशवाह ने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा के प्रति आभार व्यक्त किया है। पोहरी ओर करेरा विधानसभा में इन विकास कार्यों को मिली बजट में मंजूरी पोहरी ओर करेरा विधानसभा में 9 विकास कार्यों को बजट में मंजूरी मिली है।

जिसमें पिपरसमा से बिलौआ मार्ग व्हाया छर्च 63 किलोमीटर (63करोड़), शिवपुरी जिले में मगरौनी-नरवर के बीच सिंध नदी पद जलमग्नीय पुल का निर्माण (35.91 करोड़), डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर मार्ग के कि.मी. 61/2 में वृहद पुल का पुनर्निमाण (59.91 करोड़), मगरोनी तिराहा से अस्पताल होते हुए बस स्टेंड तक सी.सी. रोड 0.8 किलोमीटर (1.0 करोड़), करैरा-भितरवार रोड़ मुडैनी होते हुए सिद्धेश्वर तक निर्माण 3.5 किलोमीटर (4.7 करोड़), गोवरा से गोंदरी मार्ग 2 किलोमीटर (1.77 करोड़), झिरी बस स्टैण्ड से मुस्लिम बाजार होतु हुए नगर रोड़ तक मार्ग 2 किलोमीटर (2.01 करोड़), सतनवाड़ा-नरवर मार्ग के कि.मी. 14/4 सिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य (54.38 करोड़), ह॥ 27 से साँड बिलहरी मार्ग 53 किलोमीटर (100 करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृतियों से क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों को गति मिलेगी तथा आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी।

14 मार्च 2026 की नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी

क्यूँ न लिखूँ सच/ राजकुमार शर्मा (कटारे)/ शिवपुरी ,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी न्यायालयों में लंबित एवं मुकदमापूर्व (प्रीलिटिगेशन) प्रकरणों के निराकरण हेतु नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू तथा 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही आंकलित राशि के भुगतान में चूक होने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही भुगतान में विलंब होने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार न्यायशुल्क वापस किए जाने का भी प्रावधान है। संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे उक्त अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 779 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना, जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी

क्यूँ न लिखूँ सच/ हाकम सिंह रघुवंशी/ विदिशा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 779 तीर्थ यात्री भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए। इस अवसर पर विदिशा रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों और उत्साहपूर्ण माहौल में उन्हें यात्रा के काटकर बोगी में प्रवेश विदिशा विधायक तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होने वाले की बोगी में प्रवेश कराने हेतु फीता काटा अर्चना की हैं कार्यक्रम में जिला पंचायत रघुवंशी विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा द्वारा विशेष रवाना किया गया। उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ मिल रहा है, आस्था पूर्ण हो रही है। रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों एवं परिजनों द्वारा यात्रियों का गया। इस दौरान यात्रियों में विशेष उत्साह शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रशासन सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए आवश्यक हैं। यात्रा के दौरान भोजन, चिकित्सा एवं व्यवस्था भी की गई है। उल्लेखनीय है कि के तहत जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को

का भव्य स्वागत किया गया लिए विदाई दी गई। फीता श्री मुकेश टण्डन ने अयोध्या तीर्थयात्रियों को स्पेशल ट्रेन और नारियल फोड़कर पूजा अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश और विदिशा नगर पालिका ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर को शुभकामनाएं देते हुए कहा से वरिष्ठ नागरिकों को जिससे उनकी वर्षों पुरानी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुष्पमालाओं से स्वागत किया देखने को मिला और उन्होंने द्वारा यात्रियों की यात्रा को व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई अन्य मूलभूत सुविधाओं की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई जा रही है, जिससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। गौरतलब हो कि जिले के सभी तीर्थ यात्रीगण अयोध्या में दर्शन उपरांत 23 फरवरी को वापस विदिशा पहुंचेंगे।

हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हो - रघुवंशी

क्यूँ न लिखूँ सच/ हाकम सिंह रघुवंशी/ सामान्य सभा की बैठक में जनहितैषी विषयों पर गहन समीक्षा व निर्णय लिए गए विदिशा ,दिनांक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी की अध्यक्षता में बुधवार को जिपं की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में हुई इस बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगण, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोड़िया सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रघुवंशी ने हितग्राहीमूलक योजनाओं को क्रियान्वित कराने वाले विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कार्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य को आयोजन की जानकारियां पूर्व में विधिवत् रूप से अवगत कराई जाएं। पूर्व की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों पर विभागो के अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित कार्यो की अद्यतन जानकारियां सांझा की गई।

बैठक में जनहितैषी मुद्दो पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिए गए है जिसमें प्रमुख रूप से ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना हो को ध्यानगत रखते हुए कार्ययोजना के अनुरूप समय सीमा में कार्यो का संपादन कराया जाना सुनिश्चित हो। विकासखण्ड स्तर पर जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ द्वारा दिए गए है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त बैठक को संबंधित जनपद सीईओ कॉर्डिनेट करेंगे। एक दिन में दो जनपदो में इस प्रकार की बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश दिए गए है। उक्त बैठक में नल जल योजना के कार्यो के संपादन हेतु जल निगम द्वारा पाइप लाइन डालने हेतु जिन सडको की खुदाई गई है उनके मरम्मत कार्यो की भी अद्यतन जानकारियों की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। आज सम्पन्न हुई बैठक में आजीविका मिशन, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और जिला पंचायत 15वें वित्त आयोग के कार्यो की समीक्षा गई है।

संक्षिप्त समाचार

शमशाबाद लोक सभा सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जनसेवा ही संकल्प: आपकी समस्याओं का समाधान, हमारी प्राथमिकता!

क्यूँ न लिखूँ सच/ हाकम सिंह रघुवंशी/ विदिशा आज सागर स्थित 'सांसद संवाद केंद्र' पर उपस्थित रहकर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, कार्यकर्ताओं और आत्मीय जनों से भेंट की। संवाद के दौरान क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याओं और विकास संबंधी सुझावों से

अवगत कराया। मैंने प्राप्त सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण हेतु निर्देशित किया है। जनता की सेवा और उनके जीवन को सुलभ बनाना ही मेरा मुख्य ध्येय है। आप सभी का स्नेह और विश्वास ही मुझे निरंतर कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।

9 माह की गर्भवती ने पति के साथ लगाई फांसी, पहले बच्चे के इंतजार में था परिवार

जुनावई थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक ही साड़ी के फंदे बनाकर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। विवाहिता नौ माह की गर्भवती थी। 2 साल पहले शादी हुई थी। गांव खेड़ामानी निवासी खोराज यादव (25) पुत्र प्रेमपाल यादव और उसकी पत्नी सरोज (22) के शव मंगलवार सुबह करीब आठ बजे कमरे में एक ही साड़ी से बने फंदों पर लटके मिले। सरोज नौ माह की गर्भवती थी और यह दंपती का पहला बच्चा था। सुबह देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नहीं खुलने पर

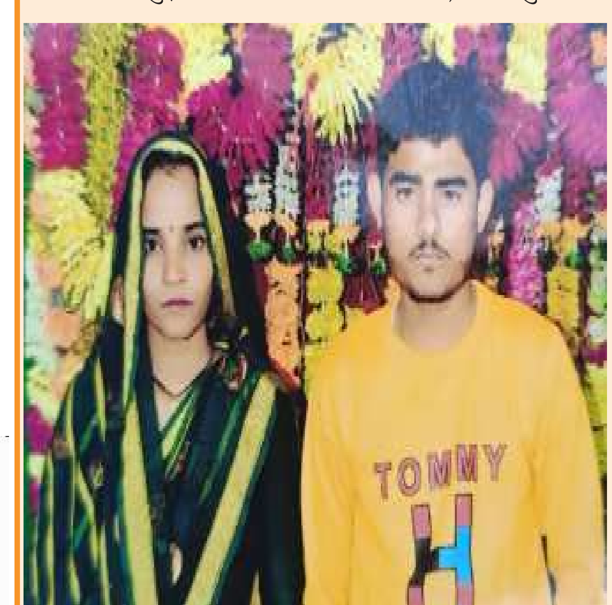

जैसे-तैसे दरबाजा खोला। दोनों के शव एक ही साड़ी से बने फंदों पर लटके देख परिवार में कोहराम मच गया। सरोज का मायका धनारी थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी में है। दो वर्ष पूर्व दोनों की शादी हुई थी। परिजनआत्महत्या की बजह नहीं बता सके। ग्रामीणों में चर्चा है कि खोराज शराब का आदी था और इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मृतक का छोटा भाई राजेंद्र एक दिन पहले ही दिल्ली से गांव लौटा था। मां कठोरी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन परिजनों ने कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया। इसके बाद आपसी सहमति से दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गर्भवती पत्नी और पति द्वारा फंदे पर लटककर जान देने की वजह को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं लेकिन कोई खुलकर नहीं बता रहा कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पति पत्नी ने फंदे पर लटककर जान दे दी। बड़ी बात यह कि मां की कोख में पल रहे मासूम की भी दुनिया देखने से पहले ही मौत हो गई। खेत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव-बबराला,अमृत विचार: जुनावई थाना क्षेत्र के गांव अल्लीपुर में मंगलवार को 19 वर्षीय दुर्वेश यादव पुत्र भूदेव यादव का शव घर से करीब आधा किलोमीटर दूर गेहूं के खेत में नीम के पेड़ से लटका मिला। सुबह करीब 5:45 बजे पीआरवी को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान उसकी जेब से नरौरा से बैरपुर तक का रोडवेज बस टिकट मिला। परिजनों के अनुसार वह नोएडा में काम करता था और हाल ही में गांव लौटा था। थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान ने बताया कि दुर्वेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Men are increasingly seeking cosmetic surgery to look attractive, willing to spend lakhs of rupees.

Beauty and grooming were often associated with women, but this perception is rapidly changing. In America, men are so obsessed with looking attractive that they are willing to spend lakhs of rupees to achieve it. Statistics from especially liposuction, a priority. Men attractive. More than 21,000 men in pressure is driving men's focus on in front of the mirror or enhancing If so, these new statistics from the US looking smart and attractive that they is such that beauty treatments, once considered an essential part of men's Achieving Desired Fitness by Catanzarite, a New Jersey resident, rapidly increased after the age of 20. calorie counting to a no-carb diet and each time it came back. Exhausted, approximately ?1.3 million on chest, stomach, and waist. Ross is Underwent Surgery - Thousands of more than 21,000 men in the US will social media, HD videos, and the men increasingly conscious of their men no longer view cosmetic surgery means of boosting self-confidence and

2024 show that men have made beauty treatments, are spending lakhs on cosmetic surgery to look the US underwent liposuction in 2024. Social media fitness and grooming. Do you think spending time their beauty through surgery is only for women? will surprise you. Men there are so obsessed with are willing to spend lakhs of rupees. The situation considered exclusively for women, are now being fitness and grooming. Let's learn more about this. Spending ?1.3 Million - The story of Ross is a perfect example of this change. Ross's weight He tried everything possible to lose weight—from intermittent fasting. He lost weight four times, but he opted for surgery in 2019. He spent liposuction, which removed excess fat from his now extremely happy with his results. 21,000 Men men like Ross are now following this path. By 2024, undergo liposuction surgery. Experts believe that constant pressure to be seen on camera have made looks. Renowned Dr. Anthony Barlet explains that as merely a means of "grooming," but rather as a improving their physique. They are spending anywhere from 300,000 to 100,000 rupees. Spending millions and age-specific choices: Robert Tice of Portland has spent approximately 2.5 million rupees to shape his body. He first lost 50 kg through bariatric surgery, then underwent a tummy tuck in 2023 and a chest lift in 2024. According to plastic surgeon Dr. Sean McNally, men's preferences vary with age: Young men in their 20s and 30s focus on improving the shape of their jawline and chin. Men in their 40s and 60s resort to surgery to maintain facial contours. From eyes to hair, the desire to change everything – not just liposuction, men are now transforming themselves from head to toe.

Is your cooking oil harming your liver? Repeated heating is dangerous.

Excessive or improper use of seed oils used in Indian kitchens can harm the liver. They contain high amounts of omega-6 fatty acids, and the toxic compounds formed by repeated heating increase the risk of fatty liver. To and avoid fried foods. High omega-6 heated oil creates toxic compounds in fatty liver. Mustard, peanut, or tempering and frying. Food in Indian ever considered that these daily oils research suggests that excessive and diseases. Let's understand how. What seeds. These primarily include oil. They are rich in omega-6 fatty when the amount of omega-6 in our The liver metabolizes fat and controls refined seed oil or fried foods, fat liver disease. Reheating oil is a major particularly harmful. Repeatedly compounds like aldehydes and detoxifying the body, these toxins and fried snacks often use reused oil,

protect your liver, limit your oil use, avoid reheating, content in seed oils can harm the liver. Repeatedly the liver. Using the wrong oil increases the risk of sunflower oil is often used in our kitchens for homes seems incomplete without them, but have you can take a toll on your liver health? Yes, recent improper use of these oils can cause serious liver are seed oils? Seed oils are oils extracted from plant mustard oil, sunflower oil, peanut oil, and soybean acids. While essential for the body, problems arise diet exceeds that of omega-3. Their effect on the liver: cholesterol. When we consume excessive amounts of accumulates in liver cells, increasing the risk of fatty risk: We often reheat leftover oil in a pan, which is reheating oil at high temperatures creates toxic oxidized fats. Since the liver is responsible for directly impact its function and structure. Street food which can cause liver inflammation and metabolic disorders. A high diet of omega-6 and a low intake of omega-3 can increase inflammation, which is linked to obesity, insulin resistance, and fatty liver. Should you switch oils? This doesn't mean you should completely avoid mustard or peanut oil; rather, using cold-pressed oil in moderation may be safe. The real problem lies in excessive oil consumption, repeated heating, and eating foods high in refined carbohydrates. Therefore, to protect your liver, be careful with your oil use. Avoid fried foods from outside, and avoid reheated oil.

Will relationships now have an expiration date? What is the new dating trend, the "sunset clause?"

A new trend in dating today called the "sunset clause" is gaining popularity among young people. In this, two people mutually agree on a time limit for the relationship. If the relationship doesn't progress or doesn't become without any bitterness. A sunset relationship, saving time and world, dating practices are rapidly new trend called the sunset clause is someone on a dating app, instead of months without any results, you set clause is and why young people are Business contracts typically include meaning the agreement practice is now being followed in the mutually agree on an expiration they understand each other and is no progress in the relationship serious about the future, they will clause in dating? Business contracts

serious within this timeframe, they can part ways clause sets a deadline at the beginning of the emotional exhaustion. In today's fast-paced and digital changing. In this era of ghosting and situationalism, a gaining popularity among young people. If you meet chatting for hours and dragging on a relationship for a time limit in advance. Let's understand what this so fond of it. What is a sunset clause in dating? clauses that set a time limit for the partnership, automatically ends after a certain period. A similar dating world. When two people start dating, they date, such as six months or a year. During this time, spend time together. The clause stipulates that if there within the stipulated time, or if both partners are not separate without any bitterness. What is a sunset typically include clauses that set a time limit for the partnership, meaning the agreement automatically ends after a certain period. A similar practice is now being followed in the dating world. When two people start dating, they mutually agree on an expiration date, such as six months or a year. During this time, they get to know each other and spend time together. The clause stipulates that if there is no progress in the relationship within the stipulated time, or if both partners are not serious about the future, they will separate without any bitterness.

Alia Bhatt will dazzle on the stage of the BAFTA Awards, with the Love and War actress given a significant responsibility.

The winners of the International Film Awards (BAFTA) will be announced soon. The British Film Academy is fully preparing for the ceremony and has now released the list of award presenters, which includes B-town actress Alia Bhatt. The BAFTA Awards winners will be announced soon. Alia Bhatt has been given a significant responsibility for the award: this Indian film has been nominated for the BAFTA Awards this year. The British Film Academy will announce this year's awards very soon. A few days ago, the list of films nominated for the 2026 BAFTA Awards was released, and now the list of award presenters has also been revealed, which includes the name of Hindi cinema's female superstar, Alia Bhatt. At the 79th BAFTA Awards, Alia will share the stage with numerous Hollywood celebrities and bring glory to Indian cinema. Let us know who are those celebrities with whom Alia's name has been included as a BAFTA Award presenter. Alia Bhatt's name is associated with these celebrities. The winners of the BAFTA Awards 2026 will be announced on February 22. The British Film Academy is busy preparing for this. On Tuesday, the list of award presenters has also been released by BAFTA, in which Alia Bhatt is the only Indian celebrity present. Apart from them, big superstars of Hollywood cinema will be present at the BAFTAs this year as award presenters, whose names are as follows - Bryan Cranston, Aaron Pierre, Cillian Murphy, Aimee Lou Wood, Alicia Vikander, Noah Jupe, Olivia Cooke, Patrick Dempsey, Regé-Jean Page, Ethan Hawke, Gillian Anderson, Glenn Close, Hannah Waddingham, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Kerry Washington, Little Simz, Maggie Gyllenhaal, David Johnson, Delroy Lindo, Emily Watson, Stormzy, Warwick Davis, Erin Doherty, Stellan Skarsgård, Mia McKenna-Bruce, Michael B. Jordan, Miles Catton, Millie Alcock, Minnie Driver, Monica Bellucci, Sadie Sink and Riz Ahmed. It is worth noting that before Alia Bhatt, Bollywood actress Deepika Padukone has also performed the responsibility of award presenter at the BAFTAs Awards ceremony in the year 2024. Apart from this, if we look at Alia Bhatt's upcoming film, its name is Love and War, which is being directed by Sanjay Leela Bhansali. This Indian film got nominated in BAFTA - The name of the Indian film which has been nominated for the 79th edition of International Film Awards BAFTA is Boong. This movie, which is going to be released in the year 2024, is directed by Laxmipriya Devi, while Farhan Akhtar has taken over the production. Let us tell you that this is a Manipuri language drama movie, which has been nominated for the Best Children and Family Film category of BAFTA Award 2026.

Romeo is hard to stop! A massive earnings battle ensued on Tuesday.

Actor Shahid Kapoor and Tripti Dimri's new film, O Romeo, is currently dominating the big screen. On its fifth day of release, the movie's box office collections saw a huge jump. O Romeo is holding its own at the box office. On the fifth day, the earnings charts changed completely - Shahid Kapoor's latest film, O Romeo, released in theaters on Valentine's Day. O Romeo, the latest film to be released in theaters on Tuesday, is currently generating considerable buzz. Starring Shahid Kapoor and Tripti Dimri, the film performed exceptionally well in Monday's box office, and now, on Tuesday, it has posted a strong box office collection. Let's find out how O Romeo performed commercially on its fifth day of release and how many crores it earned on the working day. O Romeo did wonders on Tuesday - After delivering successful films like Kaminey and Haider, actor Shahid Kapoor has returned with director Vishal Bhardwaj. O Romeo has received positive reviews from critics and audiences, giving it a strong start at the box office. After grossing over ?37 crore (approximately $37 million) in its opening weekend, it continued its strong performance on its fifth day of release. According to a report by SacNilc, the film earned an estimated ?55 million (approximately $50 million) on Tuesday, which is considered quite impressive considering the non-holiday situation. O Romeo's earnings increased on Tuesday compared to Monday, suggesting that Shahid Kapoor's film has truly won over audiences. Its total box office collection has now surpassed ?45 crore (approximately $45 million). Consequently, O Romeo could easily surpass the ?50 crore (approximately $50 million) mark by the second weekend. The film also stars Nana Patekar, Farida Jalal, Tamannaah Bhatia, Avinash Tiwari, and Vikrant Massey in pivotal roles. A thrilling gangster love story - O Romeo tells the story of Hussain Ustra, a renowned gangster in Mumbai. Love plays a role in his life, changing it completely. However, the makers have added a significant amount of fiction, which adds a dramatic twist to the story. Overall, O Romeo is a must-watch film, showcasing both love and war.

Will Rani Mukerji show her khaki-clad might in Mardaani 4? The director hinted at the fourth installment of the franchise.

After the success of Mardaani 3, everyone is eagerly awaiting whether Rani Mukerji will be seen flaunting her khaki-clad might in Mardaani 4. Now, Mardaani 3 director Abhiraj Minawala has spoken openly about this matter. Will Mardaani 4 come after Mardaani 3? Director Abhiraj Minawala spoke about the Mardaani franchise. Yash Raj Films' successful franchise, Mardaani 3, was released after a long wait. Commercially, the Rani Mukerji-starrer Mardaani 3, performed exceptionally well at the box office. This has sparked speculation about whether the makers will continue the story of the Mardaani franchise and bring a fourth installment. Recently, Mardaani 3 director Abhiraj Minawala spoke openly about this matter. Let's find out what Abhiraj has to say about Mardaani 4. Will there be a Mardaani 4? After the success of Mardaani 3, director Abhiraj Minawala recently spoke with news agency ANI. During this, he was asked a crucial question about Mardaani 4. Abhiraj said, "In my opinion, Mardaani 4 should definitely be made. Furthermore, there are many films that should definitely be made. Mardaani 1 and Mardaani 2 inspired us to make a third installment. However, it's worth noting that Mardaani 2 was released in 2019, and now, seven years later, the third installment has arrived. The most important thing for making Mardaani 4 is having a strong script and excellent content." Thus, Abhiraj Minawala has given a vague answer regarding the making of Mardaani 4. This statement clearly indicates that Rani Mukerji may or may not be confirmed in the role of female police officer Shivani Shivaji Roy in the future. It's worth noting that the Mardaani franchise began in 2014. How did Mardaani 3 perform? Rani Mukerji-starrer Mardaani 3 was released in theaters on January 30th. Since then, the movie has performed well at the box office, earning close to ?48 crore (approximately $4.8 billion).